



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 4223/2026

वीरेन्द्र कुमार

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

भारत संघ एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : सिद्धार्थ खरे

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., आदर्श भूषण, गौरव बिशन

न्यायालय संख्या- 32

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ खरे, प्रत्यर्थी-1 के अधिवक्ता श्री गौरव बिशन और प्रत्यर्थी-2, 3 और 4 के अधिवक्ता श्री आदर्श भूषण के अधिवक्ता श्री सात्विक चौधरी को सुना।

2. वर्तमान प्रकरण में कुछ तथ्य विवाद के दायरे में नहीं हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 452, 354 (ए) (1) (i), 504, 506 आईपीसी, 7/8 पॉक्सो अधिनियम और 3 (2) (v) एससी/एसटी अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन नूरिया, जिला पीलीभीत में एफआईआर संख्या 0427 दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद 02.11.2018 को एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि एक विरोध याचिका के आधार पर एक प्रकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था और उसके बाद संज्ञान लिया गया था और याचिकाकर्ता के खिलाफ समन जारी किया गया था। बाद में याचिकाकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर करके संज्ञान और समन के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जो असफल रहा और आपराधिक मुकदमा चलाया गया।

3. आपराधिक मुकदमे के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता ने भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा जारी दिनांक 08.01.2024 के एक विज्ञापन के अनुसरण में तकनीकी (सी) (इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल) के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जिसमें वह सफल रहा और नियुक्ति पत्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 13.07.2024 जारी किया गया और वह शामिल हो गया। दिनांक 05.08.2024 को एक सत्यापन प्रपत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें पैरा 12(ii) में एक घोषणा के विरुद्ध क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया है? , याचिकाकर्ता ने नहीं घोषित किया है जब स्वीकार किया गया है कि उस समय याचिकाकर्ता एक आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहा था जो अभियोजन पक्ष के गवाहों की रिकॉर्डिंग के चरण में था और याचिकाकर्ता एक आरोपी के रूप में पेश हो रहा था।

4. उपरोक्त परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता द्वारा की गई घोषणा बिल्कुल गलत थी, बल्कि यह एक गलत बयानी थी।

5. आपराधिक मुकदमे में याचिकाकर्ता को बाद में निर्णय और आदेश दिनांक 22.12.2025 द्वारा इस आधार पर बरी कर दिया गया था कि पीडब्लू-1, यानी पीड़ित ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

6. बरी करने का उपरोक्त आदेश पारित होने से पहले याचिकाकर्ता को 07.07.2025 को कारण बताओ नोटिस दिया गया था कि चूंकि उसने गलत घोषणा की है, इसलिए मौजूदा प्रमाणित स्थायी आदेशों के खंड 15.1 (xxi) के संदर्भ में उसकी सेवाओं को समाप्त क्यों नहीं किया जाए।

7. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उसने 11.07.2025 को उपरोक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया है और बाद में एक अन्य कारण बताओ नोटिस पर उसने दिनांक 04.02.2026 को एक विशिष्ट बयान के साथ जवाब प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया था, इस तरह लंबित मुकदमे के बारे में खुलासा नहीं करने के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का कोई कानूनी परिणाम नहीं होगा, लेकिन उसके उत्तरों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया।

8. याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही अंततः समाप्त हो गई और अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने दिनांक 13.02.2026 का आदेश पारित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता की सेवाओं को नोटिस के बदले में नोटिस या मुआवजे के भुगतान के बिना समाप्त कर दिया गया क्योंकि यह सत्यापन प्रपत्र में दिए गए झूठे बयान का प्रकरण था।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त संदर्भित तथ्यों पर विवाद नहीं किया है और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न स्पष्टीकरण/उत्तर प्रस्तुत किए हैं और साथ ही बरी करने का आदेश भी रिकॉर्ड पर रखा गया था, फिर भी आक्षेपित आदेश के माध्यम से उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य में



सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसलों पर भरोसा किया। एआईआर 2016 एससी 3598, उमेश चंद्र यादव बनाम महानिरीक्षक और मुख्य सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली और अन्य। 2022 (14) एससीसी 244, पवन कुमार बनाम भारत संघ और अन्य (2023) 12 एससीसी 317 और रवींद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2024) 5 एससीसी 264 में कहा गया है कि सत्यापन प्रपत्र में आपराधिक मुकदमे का खुलासा न करना घातक नहीं माना जा सकता है क्योंकि विभागीय कार्यवाही के दौरान उसे बरी कर दिया गया था और उसी का आदेश रिकॉर्ड पर रखा गया था।

10. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह एक ऐसा प्रकरण है जहां याचिकाकर्ता ने सत्यापन प्रपत्र में गलत घोषणा की है। एक आपराधिक मुकदमे का सामना करने के बावजूद, उन्होंने घोषणा के खिलाफ नहीं का उल्लेख किया है क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया है?, जो मौजूदा प्रमाणित स्थायी आदेशों के खंड 15.1 (xxi) का स्पष्ट उल्लंघन है और संदर्भ के लिए इसे इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“15.1 (xxi) - नियुक्ति/सत्यापन प्रपत्र के लिए उसके आवेदन में किए गए झूठे बयान या रोजगार के समय या चिकित्सा परीक्षा के समय या रोजगार के दौरान अपनी पिछली सेवा के बारे में तथ्यों को छिपाना या कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से की गई घरेलू जांच के समय झूठे बयान देना या साक्ष्य को दबाना।

11. याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता है कि सत्यापन फॉर्म भरे जाने पर उसे लंबित मुकदमे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने भारत संघ और अन्य बनाम शिशु पाल @ शिव पाल, 2024 आईएनएससी 550 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एक फैसले पर भरोसा किया।

12. मैंने उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

13. उपरोक्त संदर्भित तथ्य इस बात पर अधिक विवाद नहीं करते हैं कि याचिकाकर्ता ने सत्यापन प्रपत्र में गलत घोषणा की है क्योंकि उसने एक घोषणा के खिलाफ नहीं घोषित किया है, क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया है?, जबकि स्वीकार किया गया है कि जब 05.08.2024 को सत्यापन प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो याचिकाकर्ता गंभीर आरोपों के तहत आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहा था, हालांकि बाद में आपराधिक मुकदमा समाप्त हो गया था और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता को 22.12.2025 के फैसले और आदेश के माध्यम से बरी कर दिया गया था, साथ ही याचिकाकर्ता दावा नहीं कर सकता है कि उन्हें मुकदमे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि न केवल पहले उन्होंने संज्ञान और समन के आदेशों को चुनौती दी है और साथ ही उन्होंने मुकदमे में भी भाग लिया है।

14. याचिकाकर्ता इस बात पर विवाद करने में सक्षम नहीं हो सकता है कि यदि आवेदन या सत्यापन फॉर्म में गलत बयान दिया जाता है, तो उसकी सेवाओं को नोटिस के बदले में नोटिस या मुआवजे के भुगतान के बिना समाप्त किया जा सकता है, इसलिए, प्रत्यर्थी नियोक्ता होने के नाते निर्णय लेने के हकदार थे, क्या सत्यापन प्रपत्र में गलत घोषणा को बाद की घटनाओं पर विचार करते हुए अनदेखा किया जा सकता है, यानी, आपराधिक मुकदमे में बरी करने का आदेश।

15. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का पहला तर्क कि उनके विभिन्न उत्तरों पर विचार नहीं किया गया था, इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा क्योंकि याचिकाकर्ता ने सत्यापन प्रपत्र में गलत घोषणा की है जो प्रतिकूल आदेश को आमंत्रित कर सकता है।

16. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का दूसरा तर्क यह है कि बाद की घटना के आधार पर गलत घोषणा को नजरअंदाज किया जा सकता है कि अब याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णय प्रकरण के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किए गए हैं और गलत घोषणा करने की त्रुटि को या तो आरोपों से बरी करने के बाद के तथ्यों को तुच्छ होने के आधार पर माफ कर दिया गया था, जबकि वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ नैतिक अधमता के गंभीर आरोप थे। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णयों में, नियोक्ता के पास उपलब्ध विवेक पर विवाद नहीं किया गया है और सत्यापन प्रपत्र में कोई अस्पष्टता नहीं थी।

17. न्यायालय अवतार सिंह (पूर्वोक्त) पर भी ध्यान देता है, जिसमें टिप्पणियां और निर्देश तब दिए गए थे जब सत्यापन प्रपत्र से पहले बरी कर दिया गया था, जबकि वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता को सत्यापन प्रपत्र के बाद और बाद में जांच के लंबित रहने के दौरान बरी कर दिया गया था।

18. रवींद्र कुमार (पूर्वोक्त) में विभिन्न निर्णयों का हवाला देने के बाद न्यायालय यह भी ध्यान देता है कि आईपीसी की धारा 324, 352, 504 के तहत आपराधिक मुकदमा तुच्छ प्रकृति के अपराध होने के कारण था, जबकि वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता को नैतिक अधमता के गंभीर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपराध के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ा है, इसलिए, वर्तमान प्रकरण के तथ्य याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णयों के तथ्यों से अलग हैं।

19. उपरोक्त परिस्थितियों में, न्यायालय प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता, यानी **शिशु पाल (पूर्वोक्त)** द्वारा उद्धृत एक निर्णय पर ध्यान देता है, जिसमें समान प्रकृति के तथ्यों पर विचार किया गया था। उक्त प्रकरण में अवलंबी को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 447, 332, 427, 504, 506 आईपीसी और 3(1) के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ा है। गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 हालांकि बाद में उसे बरी कर दिया गया था, जबकि वर्तमान प्रकरण में आरोप अधिक गंभीर थे, अर्थात्, धारा 452, 354 (ए) (1) (i), 504, 506 आईपीसी के तहत, 7/8 पॉक्सो अधिनियम और एससी/एसटी अधिनियम के 3(2)(v). **शिशु पाल (पूर्वोक्त)** के प्रासंगिक पैराग्राफ इसके बाद पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

“21. अंततः, किसी उम्मीदवार/कर्मचारी के पूर्ववृत्त के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य नियोक्ता को विषय पद के लिए उम्मीदवार/कर्मचारी की उपयुक्तता का पता लगाने में सक्षम बनाना है। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम भूपेंद्र यादव, (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1181 (हम में से एक, हिमा कोहली, जे द्वारा लिखित) अवतार सिंह (पूर्वोक्त) में निर्णय का हवाला देते हुए, निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

16. जैसा कि उपरोक्त निर्णय से समझा जा सकता है, एक नियोक्ता के पास एक उम्मीदवार द्वारा किए गए प्रकटीकरण में चूक को समाप्त करने या माफ करने का विवेक है। ऐसा करते समय, नियोक्ता को विवेक के साथ कार्य करना चाहिए, पद की प्रकृति और निर्वहन के लिए आवश्यक कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए। पद जितना अधिक होगा, मानकों को लागू करने के लिए अधिक कठोर होना चाहिए। यहां तक कि अगर एक सच्चा खुलासा किया गया है, तो नियोक्ता एक उम्मीदवार की फिटनेस की जांच करने के अपने अधिकार के भीतर है और एक निष्कर्ष आपराधिक प्रकरण में, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखें और सत्यापित करें कि क्या बरी करना सम्मानजनक है या तकनीकी कारणों से लाभ बढ़ाया गया है। यदि नियोक्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अवलंबी संदिग्ध चरित्र का है या पद के लिए अयोग्य है, तो उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता है या सेवा में जारी रखा जा सकता है।



22. हम दयाशंकर यादव बनाम दया शंकर यादव बनाम भारत संघ और अन्य, (2010)

14 एससीसी 103 में निर्णय का भी लाभप्रद रूप से हवाला दे सकते हैं। जहां पद के लिए उपयुक्तता के संबंध में अपने पूर्ववृत्त के संबंध में एक उम्मीदवार से प्राप्त जानकारी की जांच के परिणामों के रूप में निम्नानुसार चर्चा की गई है:

15. जब कोई कर्मचारी या भावी कर्मचारी सत्यापन फॉर्म में घोषणा करता है, चरित्र और पूर्ववृत्त से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है, तो उसके सत्यापन से निम्नलिखित में से कोई भी परिणाम हो सकता है:

(ए) यदि घोषणाकर्ता ने सकारात्मक में प्रश्नों का उत्तर दिया है और किसी आपराधिक प्रकरण का विवरण प्रस्तुत किया है (जिसमें उसे साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोषी ठहराया गया था या बरी कर दिया गया था), तो नियोक्ता उसे रोजगार की पेशकश करने से इनकार कर सकता है (या यदि पहले से ही परिवीक्षा पर कार्यरत है, तो उसे सेवा से छुट्टी दे दी गई है), यदि वह उस अपराध/अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अयोग्य पाया जाता है जिसमें वह शामिल था।

(बी) दूसरी ओर, यदि नियोक्ता को पता चलता है कि घोषणाकर्ता द्वारा खुलासा किया गया आपराधिक प्रकरण उन अपराधों से संबंधित है जो तकनीकी थे, या ऐसी प्रकृति का जो घोषणाकर्ता की रोजगार के लिए फिटनेस को प्रभावित नहीं करेगा, या जहां घोषणाकर्ता को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था और दोषमुक्त कर दिया गया था, तो नियोक्ता इस तथ्य को अनदेखा कर सकता है कि घोषणाकर्ता पर एक आपराधिक प्रकरण में मुकदमा चलाया गया था और उसे नियुक्त करने या उसे रोजगार में जारी रखने के लिए आगे बढ़ सकता है।

(सी) जहां घोषणाकर्ता ने नकारात्मक में प्रश्नों का उत्तर दिया है और सत्यापन पर यह पाया जाता है कि उत्तर झूठे थे, नियोक्ता घोषणाकर्ता को नियुक्त करने से इनकार कर सकता है (या उसे छुट्टी दे सकता है, यदि पहले से ही नियोजित है), भले ही घोषणाकर्ता को आरोपों से मुक्त कर दिया गया हो या बरी कर दिया गया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उसके चरित्र पर असर डालने वाली भौतिक जानकारी



का दमन या गैर-प्रकटीकरण होता है, तो यह स्वयं घोषणाकर्ता को नियुक्त नहीं करने का एक कारण बन जाता है।

(डी) जहां सत्यापन प्रपत्र या सत्यापन प्रपत्र में उचित या पर्याप्त प्रश्न नहीं होते हैं जिनमें घोषणाकर्ता को किसी आपराधिक कार्यवाही में अपनी संलिप्तता का खुलासा करने की आवश्यकता होती है, या जहां उम्मीदवार को सत्यापन रोल/सत्यापन प्रपत्र में घोषणाएं देते समय आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के बारे में पता नहीं था, तो उम्मीदवार को इसमें दोष नहीं पाया जा सकता है, प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के लिए। लेकिन अगर नियोक्ता अन्य माध्यमों से (जैसे पुलिस सत्यापन या शिकायतें, आदि) घोषणाकर्ता की भागीदारी के बारे में सीखता है, तो नियोक्ता उपरोक्त पाठ्यक्रमों (ए) या (बी) का सहारा ले सकता है।

23. राजस्थान राज्य विधि प्रसारण निगम लिमिटेड और अन्य बनाम अनिल कांवरिया, (2021)10 एससीसी 136 में, इस न्यायालय ने राय दी थी कि यहां तक कि जहां बाद में बरी किया गया था, वहां भी एक कर्मचारी गलत जानकारी प्रस्तुत करने या लंबित आपराधिक प्रकरण से संबंधित भौतिक तथ्यों को छिपाने में लिप्त होने के अधिकार के प्रकरण के रूप में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है। नियोक्ता के दृष्टिकोण से ऐसे कर्मचारी की विश्वसनीयता में संध का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया गया है:

“14. इस मुद्दे / प्रश्न पर नियोक्ता के दृष्टिकोण से दूसरे दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। सवाल इस बारे में नहीं है कि क्या कोई कर्मचारी तुच्छ प्रकृति के विवाद में शामिल था और क्या उसे बाद में बरी कर दिया गया है या नहीं। सवाल ऐसे कर्मचारी की विश्वसनीयता और/या विश्वसनीयता के बारे में है, जिसने रोजगार के प्रारंभिक चरण में यानी घोषणा/सत्यापन प्रस्तुत करते समय और/या किसी पद के लिए आवेदन करते समय गलत घोषणा की और/या किसी आपराधिक प्रकरण में शामिल होने के भौतिक तथ्य का खुलासा और/या दबाकर नहीं किया। यदि सही तथ्यों का खुलासा किया गया होता, तो नियोक्ता ने उसे नियुक्त नहीं किया होता। फिर सवाल भरोसे का है। इसलिए, ऐसी स्थिति में, जहां नियोक्ता को लगता है कि एक कर्मचारी जिसने प्रारंभिक चरण में ही एक गलत बयान दिया है और/या भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं किया है और/या भौतिक तथ्यों को दबा



दिया है और इसलिए उसे सेवा में जारी नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ऐसे कर्मचारी पर भविष्य में भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, नियोक्ता को ऐसे कर्मचारी को जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ऐसे कर्मचारी को जारी रखने या न रखने का विकल्प/विकल्प हमेशा नियोक्ता को दिया जाना चाहिए। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा गया है और जैसा कि निर्णय के कैंटना में ऊपर देखा गया है, ऐसा कर्मचारी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है और/या अधिकार के प्रकरण के रूप में सेवा में जारी नहीं रह सकता है।

24. मौजूदा प्रकरण में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी की ओर से की गई दलील को स्वीकार करने में गलती की है कि अपीलकर्ताओं द्वारा 24 जून, 2014 को उसे सेवा से हटाने का आदेश पारित करने के बाद ही उसने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरण के बारे में पूछताछ की थी और बाद में, प्रत्यर्थी को आपराधिक प्रकरण संख्या 459/2011 में बरी कर दिया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उक्त टिप्पणियां रिकॉर्ड के विपरीत हैं जो स्पष्ट रूप से प्रकट करती हैं कि प्रत्यर्थी इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था कि उसके खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था, उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था और बाद में उक्त प्रकरण में अन्य सह-अभियुक्तों के साथ जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे विचारण न्यायालय ने 04 अक्टूबर 2011 को मंजूरी दी थी। उपरोक्त सभी घटनाएं 30 नवंबर, 2011 से काफी पहले हुई थीं, जिस तारीख को प्रत्यर्थी ने सत्यापन रोल भरा था। इसलिए, यह देखा जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी को एफआईआर दर्ज करने और आपराधिक प्रकरण के लंबित होने की पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद, उन्होंने सत्यापन रोल भरते समय अपीलकर्ताओं से जानबूझकर भौतिक जानकारी छिपाई थी। उन्होंने खुद को और गलत तरीके से पेश किया था जब अपीलकर्ताओं ने उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था और कारण बताओ नोटिस के जवाब में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया था, जिसके कारण अंततः उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।

25. जहां तक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों का सवाल है कि प्रत्यर्थी एक युवा व्यक्ति था और उसे सेवा से हटाने के बजाय उस पर मामूली जुर्माना लगाकर



उसके अविवेक को माफ किया जाना चाहिए, इसका उत्तर भूपेंद्र यादव (पूर्वोक्त) में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों में निहित है:

24. .. उन प्रकरण में लागू किए जाने वाले मानदंड जहां मांग की गई नियुक्ति एक कानून प्रवर्तन एजेंसी से संबंधित है, एक नियमित रिक्ति पर लागू होने वाली तुलना में बहुत अधिक कठोर होना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि एक बार इस तरह के पद पर नियुक्त होने के बाद, प्रत्यर्थी पर समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने, कानून लागू करने, हथियारों और गोला-बारूद से निपटने, संदिग्ध अपराधियों को पकड़ने और बड़े पैमाने पर जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसलिए, कानून प्रवर्तन एजेंसी में नियुक्ति की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होने वाले शुद्धता का मानक हमेशा इस साधारण कारण से उच्च और अधिक कठोर होना चाहिए कि उच्च नैतिक आचरण का कब्जा पुलिस सेवा के रूप में संवेदनशील पद पर नियुक्ति के लिए बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है।”

20. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के आधार पर जहां याचिकाकर्ता नैतिक अधमता के गंभीर आरोपों के तहत मुकदमे का सामना कर रहा था और स्वीकार करता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में गलत घोषणा की है, बरी करने के बाद के आदेश का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता अपने वाहक की शुरुआत में एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर विश्वास लगाया जा सकता है। उन्होंने गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और सत्यापन प्रपत्र में गलत घोषणा की है। इसलिए, मौजूदा प्रमाणित स्थायी आदेश के प्रासंगिक खंडों के आलोक में प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता की सेवाओं को सही ढंग से कार्य किया है और समाप्त कर दिया है और तथ्यों के साथ-साथ कानून पर उपरोक्त संदर्भित स्थिति पर विचार करते हुए, न्यायालय को आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

21. तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

28 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी)

एके